भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 866
उत्तर देने की तारीख 12.12.2022

सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की विकासात्मक/शिक्षा संबंधी कठिनाइयां

†866. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्कूलों में विकासात्मक/सीखने में कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;
(ख) क्या सरकार ने विकासात्मक शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की सहायता करने के लिए सरकारी स्कूल शिक्षण पद्धति, कर्मचारियों के व्यवहार आदि के उपयुक्त बुनियादी ढांचे का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा बच्चों में उचित शैक्षिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): भारत सरकार द्वारा तीन साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा III, V, VIII और X पर केंद्रित नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। एनएएस का अंतिम दौर 12 नवम्बर, 2021 को पूरे भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्र शामिल थे। एनएएस का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के दक्षता सूचकांक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करना है ताकि विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्यों के लिए समुचित कदम उठाए जा सकें। एनएएस 2021 के लिए राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला रिपोर्टें 25.05.2022 को प्रकाशित की गई हैं और ये http://nas.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख): शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है और समग्र शिक्षा के तहत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को उनकी वार्षिक योजना के आधार पर निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्कूल की अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य कारकों की मांग का आकलन करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी योजना विकसित करते हैं, जो यह सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सुगम पहुंच हो। ये मांगें उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती हैं।

(ग): सरकारी स्कूलों में बच्चों में उचित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. समग्र शिक्षा और पीएम पोषण की केंद्र प्रायोजित योजना को एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुरूप बनाया गया है। समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपलब्धि सर्वेक्षणों का संचालन, अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक

गतिविधियों के लिए अनुदान आदि जैसी विभिन्न पहलों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलने/उन्हें सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों के निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन और संचालन करने, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना सहित शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से कक्षा-3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त कर ले, समग्र शिक्षा के तहत बोध पठन और संख्या ज्ञान में प्रवीणता संबंधी राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) शुरू की गई है और इससे संबंधित ई-सामग्री दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जारी की गई है।

3. स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों/प्राचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0 और 3.0 एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड देने के लिए 70 संकेतकों पर आधारित मैट्रिक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) विकसित किया गया है। जिला स्तरीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) तैयार किया गया है और पीजीआई-जिला के संकलन के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

5. सीबीएसई द्वारा कक्षा 3, 5, और 8 के लिए प्रतिस्पर्धा आधारित आकलन के लिए संरचित अधिगम स्तर विश्लेषण मूल्यांकन (सफल) फ्रेमवर्क विकसित किया गया और 29 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया, जिसमें मूल अवधारणाओं, एप्लीकेशन आधारित प्रश्नों और उच्च स्तरीय विचार कौशल पर फोकस किया गया है।

6. विद्या प्रवेश- तीन माह के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल हेतु दिशानिर्देश 29 जुलाई, 2021 को जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे जब कक्षा-I में आएं तो वे एक हंसते-खेलते और प्यार भरे वातावरण से सुपरिचित हों ।

*****